



- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन के दौरे पर आज दोपहर पश्चिम बंगाल से असम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
- द्वीप समूह में पहली जनवरी, 2026 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया गया है।
- राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर कल द्वीप समूह में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
- संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने द्वीपसमूह में नई बिजली दरों को मंजूरी प्रदान की।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन के दौरे पर आज दोपहर पश्चिम बंगाल से असम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राज्य में करीब 15 हजार 600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आज पहले दिन, प्रधानमंत्री गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक बांस के बाग टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। लगभग एक लाख 40 हजार वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल प्रति वर्ष एक करोड़ 30 लाख यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। “बांस के बाग” विषय से प्रेरित यह टर्मिनल असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नदिया जिले के रानाघाट में तीन हजार दो सौ करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम हो जाएगा। जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम हो जाएगी। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को गति प्रदान करेंगी।



उपराज्यपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार द्वीप समूह में पहली जनवरी, 2026 से ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948’ के प्रावधानों के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया गया है। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी छह सौ बावन रुपए प्रतिदिन, अर्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए सात सौ तैंतीस रुपए प्रतिदिन, कुशल एवं लिपिकीय कर्मचारियों के लिए आठ सौ छप्पन रुपए प्रतिदिन जबकि अति कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी नौ सौ

उनतालीस रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं से संशोधित मजदूरी दरों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संशोधित मजदूरी दरों की प्रति श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।



कृषि विभाग, केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत द्वीप समूह में “लघु सिंचाई का विकास” योजनाएं लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तिगत किसानों और सहकारी खेती समितियों को विभिन्न प्रकार के सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऋण-सह-सब्सिडी, श्रमदान-सह-सब्सिडी और नकद-सह-सब्सिडी के रूप में होगी। ऋण-सह-सब्सिडी के लाभार्थी हिस्से की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इच्छुक किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों के कृषि उप-डिपो या क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करने होंगे। सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र द्वीपों के सभी कृषि उप-डिपो और क्षेत्रीय कृषि कार्यालयों में उपलब्ध हैं।



द्वीप समूह में कल पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुबह साढ़े आठ बजे स्वास्थ्य केंद्र जंगलीघाट में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। जिसमें बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दो बूंदें पिलाई जाएंगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ऋचा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।



संयुक्त विद्युत नियामक आयोग ने द्वीपसमूह में वित्त वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस से वर्ष दो हजार उनतीस-तीस के लिए बिजली की नई दरों को अपनी मंजूरी प्रदान की है। टैरिफ के तहत घरेलू और गैर घरेलू श्रेणियों के साथ साथ उच्च वोलटेज उपभोक्ताओं के लिए भी प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अलावा टाइम ऑफ डे टैरिफ को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत दिन के समयों में बिजली खपत के अनुसार शुल्क लागू होगा। ये दरें पहली नवम्बर दो हजार पच्चीस से लागू हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए विभागीय एवं संयुक्त विद्युत नियामक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2016 से द्वीप समूह में लागू की गई है। रबी 2025-26 सीजन के लिए पूरे द्वीप समूह में PMFBY को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है जिसमें दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान, और निकोबार में केवल कैपबेल बे क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें सभी अधिसूचित फसलों के लिए 80 प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किया गया है। वित्त का पैमाना और बीमा राशि रबी 2025-26 सीजन के लिए, PMFBY के तहत दलहन के लिए वित्त का पैमाना 59,433 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। सब्जी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर दरें भी निर्धारित की गई हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए, रबी 2025-26 के दौरान 100 प्रतिशत प्रीमियम सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार और किरायेदार किसान भी शामिल

हैं, पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि पन्द्रह जनवरी है। किसान बैंकों के माध्यम से या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।



खेल एवं युवा मामले निदेशालय, की ओर से प्रशासन द्वारा आयोजित 'बीच गेम्स-2025' का कल शुभारंभ हुआ। कारबाईन्स कोव तट पर आयोजित इस खेल का उद्घाटन मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने किया। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत नशामुक्त समाज का संदेश प्रसारित करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने युवाओं को खेल विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। बीच गेम्स 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान कई खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।



युवा मामले और खेल मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत, प्रशासन के खेल एवं युवा मामले विभाग ने 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के हिस्से के रूप में 'विकसित भारत चैलेंज ट्रैक' के राज्य स्तरीय प्रेजेंटेशन राउंड का आयोजन किया। इसमें उन छात्रों ने भाग लिया जिन्हें ऑनलाइन विकसित भारत क्विज़ और ऑनलाइन निबंध दौर जैसे कई चरणों के माध्यम से चयनित किया गया था। मंत्रालय द्वारा प्रेजेंटेशन राउंड के लिए 46 छात्रों का चयन किया गया। द्वीप समूह के विभिन्न जिलों के युवाओं ने इस राज्य स्तरीय दौर में भाग लिया।

